भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या : 66

उत्‍तर देने की तारीख : 24 नवंबर, 2014

**राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आर॰ यू॰ एस॰ ए॰) का कार्यकरण**

**66. प्रो॰ मृणाल मिरिः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्ष 2013 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को देश के सभी भागों के उच्च शैक्षिक संस्थाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संवर्धन हेतु एक माध्यम के रूप में शुरू किया गया था और केन्द्रीय परियोजना मूल्यांकन बोर्ड को इसका निगरानी प्राधिकरण बनाया जाना था;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान परिकल्पनानुसार काम कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो अभी तक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास राज्‍यमंत्री**

**(प्रो. (डॉ.) राम शंकर कठेरिया)**

**(क):** जी, हां। राष्‍ट्रीय उच्‍चतर शिक्षा अभियान (रूसा) की केन्‍द्रीय प्रायोजित योजना, पहुंच, उत्‍कृष्‍टता और समानता के लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने के उद्देश्‍यों से राज्‍यों में उच्‍चतर शिक्षा में सुधार हेतु दिनांक 3 अक्‍तूबर, 2013 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित की गई थी। रूसा, राष्‍ट्रीय स्‍तर पर मिशन प्राधिकरण, परियोजना अनुमोदन बोर्ड और राष्‍ट्रीय परियोजना निदेशालय से गठित सांस्‍थानिक वास्‍तुकला; राज्‍य स्‍तर पर राज्‍य उच्‍चतर शिक्षा परिषदों और राज्‍य परियोजना निदेशालयों; सांस्‍थानिक स्‍तर पर शासी बोर्ड या समकक्ष निकाय और परियोजना मॉनीटरिंग इकाईयों के माध्‍यम से कार्यान्वित और मॉनीटर किया जाता है।

**(ख) और (ग) :** जी, हां। आज की तारीख तक 28 राज्‍य और 5 संघ शासित प्रदेशों की रूसा में भागीदारी है, जिसमें से 19 राज्‍यों ने अपनी राज्‍य उच्‍चतर शिक्षा योजनाएं प्रस्‍तुत की है। 23 राज्‍यों और 4 संघ शासित प्रदेशों के लिए तैयारी संबंधी अनुदान के रूप में 74.04 करोड़ रू.; प्रबंध मॉनीटरिंग, मूल्‍यांकन और अनुसंधान के लिए 2.51 करोड़ रू.; 81 मॉडल डिग्री कालेजों के लिए 256.08 करोड़ रू.; 155 कालेजों के लिए अवसंरचनात्‍मक अनुदान के रूप में 154.77 करोड़ रू. और 4 राज्‍यों में 10 विश्‍वविद्यालयों के लिए 100 करोड़ रू.; एमडीसी में 8 वर्तमान कालेजों के स्‍तरोन्‍नयन के लिए 3 राज्‍यों हेतु 16 करोड़ रू.; 5 राज्‍यों में उच्‍चतर शिक्षा के व्‍यवसायीकरण और 3 राज्‍यों में साम्‍य पहलों के लिए क्रमश: 19.475 करोड़ और 6.40 करोड़ रू.; एक राज्‍य के संकाय में सुधार और संकाय की भर्ती हेतु क्रमश: 3.33 करोड़ रू. और 9.04 करोड़ रू.; कालेजों के एकीकरण द्वारा 3 राज्‍यों में 4 विश्‍वविद्यालय स्‍थापित करने के लिए 79.90 करोड़ रू.; 5 राज्‍यों मे व्‍यावसायिक कालेज स्‍थापित करने के लिए 104 करोड़ रू. की राशि अनुमोदित की गई।

**(घ) :** प्रश्‍न नहीं उठता।

\*\*\*\*\*